भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

विषय: समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतीकरण-02-अक्टूबर-2020

जल संसाधन विकास एवं सम्बद्ध विषयों से संबन्धित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है. इसकी साफ्ट कापी केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.

संलग्नक: उपरोक्त

(-/sd)

सहायक निदेशक

उप निदेशक(-/sd)

निदेशक (-/sd)

सेवा में

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

जानकारी हेतु: सभी संबन्धित केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट http://cwc.gov.in/news-clipping पर देखें

Deccan Chronicle 02-October-2020

I am ready to fight with God for water: KCR

S.A. ISHAQUI | DC
HYDERABAD, OCT. 1

Chief Minister K. Chandrashekar Rao has announced that he would not mind even fighting with God to protect the interests of agriculture and farmers in Telangana.

Speaking at a high-level meeting with officials from the water resources department at Pragathi Bhavan on Thursday, Rao recalled that the movement for separate Telangana originated from discrimination against the region in the matters of river water-sharing.

Finalising the required strategy to adopt at the apex council meeting to counter Andhra Pradesh's claims and also expose the Centre and get the rightful water share to Telangana, Rao said after the formation of a separate state, Telangana has transformed into a granary of the country and the state succeeded in strengthening the water resources sector by saving every single drop of river water.

"In the new state, there was a festive atmosphere in the agricultural sector with farmers of Telangana reaping bumper crops and becoming a role model for the entire country," said the Chief Minister, making it clear that "the rightful share of every drop of water from Godavari and Krishna rivers would be utilised optimally and without fail."

Haribhoomi 02-October-2020

5 करोड़ भारतीयों के पास हाथ धोने के लिए साफ पानी नहीं

नई दिल्ली। भारत में पांच करोड़ से अधिक भारतीयों के पास हाथ धोने की ठीक व्यवस्था नहीं है जिसके कारण उनके कोरोना से संक्रमित होने और उनके द्वारा दूसरों तक संक्रम फैलाण फैलने का जोखिम बहुत अधिक है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए 6 साल से कर्नाटक का स्टार्टअप वॉटरसाइंस इंडिया जो न सिर्फ पीने के पानी के बारे में बात कर रहा है बल्कि पानी जो हर रोज़ हमारे घरेलू कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है।

Hindustan 02-October-2020

प्रदूषण के चलते नदियों का पानी नहाने के लायक भी नहीं

बिना शोधन 66 % सीवर का पानी बहाया जा रहा

रिपोर्ट

नई दिल्ली | प्रभात कुमार

देशभर में 66 फीसदी सीवेज को शोधन के बगैर नदियों व तलाबों में बहा दिया जाता है। इतना ही नहीं, सीवेज को शोधित करने के पूरी क्षमता का भी इस्तेमाल पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल निगरानी समिति (सीएमसी) ने एनजीटी में रिपोर्ट पेश करते हुए यह जानकारी दी है।

सीवेज के दूषित पानी को शोधन के बगैर ही नदियों में बहाए जाने के कारण ही गंगा, यमुना, घाघरा, हिंडन सहित देश तमाम नदियों में प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि इसका पानी लोगों के लिए पीना तो दूर, नहाने के लायक भी नहीं बचा है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस एके गोयल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष पेश रिपोर्ट में सीएमसी ने कहा है कि 31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों से प्रतिदिन 53,696 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) सीवेज निकलता है। इन राज्यों में 1212 सीवेज शोधन सयंत्र (एसटीपी) सेर 29,566 एमएलडी सीवेज शोधन का क्षमता है। लेकिन कुल क्षमता का 62 फीसदी ही इस्तेमाल हो रहा है यानी 18330 एमलटी सीवेज का ही शोधन हो पा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में अभी 35366 एमएलडी यानी 66 फीसदी सीवेज के दूषित पानी को शोधन के बगैर ही नदियों, जलाशायों में बहा दिया जाता है जो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट में एसटीपी की क्षमता का 100 फीसदी इस्तेमाल नहीं होने के कई कारण बताए गए हैं, इनमें तकीनीकी खामी, काफी सालों से अपग्रेड नहीं होना, एसटीपी तक सीवेज का दूषित पानी की पहुंच सुनिश्चित नहीं होना बड़ी वजह है।

एनजीटी का आदेश : नदियों में न जाए गंदा पानी

एनजीटी ने रिपोर्ट में विचार करने के बाद दिल्ली,यूपी सहित देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सीवेज का पानी किसी भी हाल में नदियों में नहीं जाने दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने सभी राज्य सरकारों से एसटीपी की क्षमता बढ़ाने का भी आदेश दिया है।

एसटीपी तय मानकों पर नहीं कर रहा है काम

सीएमसी ने रिपोर्ट में कहा है कि यूपी, उतराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर सहित 10 राज्यों के 235 में से 162 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तय मानकों पर काम कर रहा है। जबकि बाकी तय मानकों की अनदेखी करके काम कर रहा है।

दिल्ली सीवेज को शोधित करने में सबसे आगे

एनजीटी में पेश रिपोर्ट में सीवेज को शोधित करने में दिल्ली सबसे आगे हैं। यहां 90 फीसदी सीवेज को शोधित किया जाता है। वहीं, सिक्कम 89, गुजरात 83, हरियाणा 82, पंजाब 80, यूपी में 76 फीसदी और बिहार में 55 फीसदी सीवेज का शोधन होता है।

Hindustan 02-October-2020

मोदी ने जल जीवन अभियान के लिए सरपंचों को पत्र लिखा

अपील

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन अभियान के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश भर के सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा कि इसके लक्ष्य को गांवों के सामुदायिक नेतृत्व की मदद से पूरा किया जा सकता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जनता और ग्राम पंचायतों से जल जीवन अभियान को जन आंदोलन बनाए जाने की अपील की। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को 29 सितंबर को पत्र लिखकर जल जीवन अभियान के और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संपर्क किया है।